On the question of what the Supreme Court has said and what the High Court has said, I will look into these things. If anyone wants to know more details about the case, I am prepared to give him.

इलेक्ट्रॉनिकी के विकास के लिये आबंटन

*223. **श्री राजूभाई ए० परमार:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान तथा आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि में इलेक्ट्रॉनिकी के विकास के लिये कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) इस आबंटन में गुजरात का कितना हिस्सा है;

(ग) गुजरात में चालू वर्ष तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान चालू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गुजरात हेतु इस क्षेत्र में स्वीकृत विदेशी तथा गैर-सरकारी निवेश के प्रसतावों का ब्यौरा क्या है?

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फेलेरियो): (क) से (घ) एक विवरण पत्र राज्य सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) इलेक्ट्रॉनिकी के विकास के लिए चालू वर्ष तथा आठवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार का परिव्यय नीचे दिए अनुसार है:—

अवधि	परिव्यय
1995-96 (सकल बजटीय सहायता)	147 करोड़ रुपए
आठवीं योजना	588 करोड़ रुपए

(ख) इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में इस केन्द्रीय परिव्यय का राज्यवार कोई विशिष्ट आबंटन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग इस केन्द्रीय परिव्यय से अपनी विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों के स्रोतों से, इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की आवश्यकताओं के आधार पर आबंटन करता है, जिसका निर्धारण विभिन्न विशेषज्ञ परिषदों तथा समितियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की परियोजनाएं तथा कार्यक्रम विशिष्ट प्रौद्योगिकी अथवा जनशक्ति के विकास के लिए मूल संरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना करने वाले या प्रायोजित परियोजनाओं की प्रकृति के होते हैं।

(ग) आठवीं योजना के दौरान गुजरात में अब तक इलेक्ट्रॉनिकी विभाग से सहायता प्राप्त परियोजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(घ) वर्ष 1992-95 की अवधि के दौरान खाली वीडियो, कैसेट, पीसी बोर्ड, कम्पैक्ट डिक्स तथा कम्पैक्ट डिस्क ड्राइव और इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) तथा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजनाओं और घरेलू क्षेत्र तथा शतप्रतिशत निर्यात उन्मुखी इकाई (ईओयू) योजना के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर का विकास करने के लिए गुजरात राज्य में इलेक्ट्रॉनिकी इकाइयों के लिए 7 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए, जिनमें प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश शामिल है।

विवरण-I

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग से सहायता प्राप्त परियोजनाएं/कार्यक्रम

क्रम० सं०	परियोजना/कार्यक्रम
मूल संरचनात्मक सुविधाओं से संबंधित	
1.	सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, गांधी नगर
2.	इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र, बड़ौदा
प्रायोजित प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाएं	
3.	कम लागत वाले डॉप्पलर वीएचएफ सोनी रेंज (डीवीओआर) तथा पारम्परिकी वीओआर (सील वीओआर) प्रणाली का विकास गुजरात संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी लि० (जीसीईएल), बड़ौदा
4.	कृषक सूचना प्रणाली प्रोटोटाइप का विकास चरण-1 इंस्टीट्यूट फार स्टडीज़ एण्ड ट्रांस्फॉरमेशन, अहमदाबाद
5.	अंकीय प्रतिबिम्ब संसाधन तकनीक के माध्यम से सूती तन्तु जाल विश्लेषक का विकास, अटीरा, अहमदाबाद
6.	पटसन यंत्रीकरण कार्यक्रम, अटीरा, अहमदाबाद
7.	वस्त्र यंत्रीकरण कार्यक्रम, अहमदाबाद वस्त्र एवं उद्योग अनुसंधान संघ (अटीरा), अहमदाबाद

जनशक्ति विकास से संबंधित:

8. 24 संस्थानों में कम्प्यूटर शिक्षण जिसमें बी०टेक, एम टेक, कम्प्यूटर अनुप्रयोग में निष्णात, (एमसीए), कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीसीए), कम्प्यूटर अनुप्रयोग में पॉलिटेक्निक उपरान्त डिप्लोमा (पीपीडीसीए) तथा डेटा प्रविष्टि प्रचालक/प्रोग्रामर शामिल है।

9. 4 स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिकी में विज्ञान निष्णात के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यक्रम

10. विश्व बैंक की सहायता से जनशक्ति प्रशिक्षण के लिए बड़ौदा तथा अहमदाबाद स्थित दो संस्थानों में समुचित सक्षमता एवं प्रशिक्षण सहित एकीकृत जनशक्ति विकास कार्यक्रम "इम्पैक्ट"

अन्य

11. 52 स्थानों पर विवेक दर्पण

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Mr. Chairman, Sir, a large number of multinational companies have already entered India in the field of computers and telecommunications. These multi-national companies are not manufacturing or assembling electronic items in India. But they are only trading in these electronic items without having any base in our country. Sir, I would like to know from the hon. Minister what steps are being taken to impress upon these multinational companies to set up their bases in India for providing after-sales service and manufacturing of these electronic items so that these equipments are serviced and sold at reasonable prices and to generate employment in India.

SHRI EDUARDO FALEIRO: Sir, before we go into multinational companies, let us consider national companies themselves. In the context of Gujarat to which this question relates, it occupies a pride of place in industrial production and it occupies number two position in the total industrial output in the country.

As far as electronic industry is concerned, it occupies the eighth position. The eighth position by itself does not speak everything because this eighth position corresponds only to 3.82 per cent of all-India production in electronic items. In exports, it corresponds to 1.82 per cent of all-India exports. Therefore, Sir, the Government of Gujarat and every State concerned must look as to how to improve the production and create incentives for the production of electronic goods in that State.

As far as maintenance and servicing of equipment are concerned, the point is well taken because unless electronic equipment in particular and other equipments in general are maintained and serviced at appropriate time and in a proper manner, the results are not going to be good.

May, I, Sir, with your permission submit that we have been able to include in the MPs Local Area Development Scheme, electronic equipments also so that Members of Parliament can disseminate information from their constituencies. As far as Members of Rajya Sabha are concerned, they choose districts. We have been suggesting to the Members of Parliament and to all concerned that when the equipment is purchased, they should also see that seller's proper maintenance and servicing facility near the area is available where the equipment will be used.

SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has given the details of the proposals for foreign and private investment in the sector of electronics for Gujarat. But the hon. Minister has not mentioned whether these proposals have already been cleared by the Foreign Investment Board of the Central Government. I would, therefore, request the Minister to indicate whether the FIB has accorded its approval to these proposals, and if not, by when approval will be granted.

SHRI EDUARDO FALEIRO: Sir, approvals have been accorded. Proposals are now actually crystallising into industries at the sites in Gujarat. They are operating that.

श्री शंकर दयाल सिंह: सभापति महोदय, यह मूल प्रश्न जो है, वह गुजरात राज्य को लेकर है। लेकिन इसका क्षेत्र पूरे देश में है और आठवीं पंचवर्षीय योजना को मुख्य रूप से इसमें लिया गया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इलैक्ट्रोनिक के क्षेत्र में इस केन्द्रीय परिव्यय का राज्यवार आबंटन आपने क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें लिखा हुआ है कि आपने स्टेटवाईज आबंटन नहीं किया है, —नम्बर एक। दूसरी बात, मैं यह जानना चाहता हूं कि वीडियो कैसेट, पी०सी० बोर्ड, कम्पेक्ट डिस्क, कम्पेक्ट डिस्क ड्राईव्ज, इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर, सोफ्टवेयर आदि में जो घरेलू उद्योग इतनी बड़ी संख्या में हमारे यहां पनप रहे है, उनकी सहायता के लिए सरकार ने कौन सी योजना बनाई है और इसमें किस तरह की सहायता अब तक दी जा रही है?

SHRI EDUARDO FALEIRO: Sir, the Government is extremely keen on developing indigenous industries, particularly, indigenous electronic industries because electronics is a matter resource. It is not just an industry. It helps every single industry and cuts across every single sector of the national economy in terms of increasing productivity, increasing transparency, efficiency and so on. Therefore, the Department of Electronics, played a promotional role on three lines: (1) Training of manpower; (2) Building of infrastructure; and (3) Supporting Research and Development. Now, the question is why it is not being done State-wise.

It is not done and, I think, for extremely good reasons. The point is not the State. The point is to create, and create very fast and in large quantities, trained man-power. Therefore, we have to identify institutions which are prepared to do this and which have the base to do this. We have identified institutions in Gujarat and they have been mentioned here in the annexure to the answer, if I am not mistaken.

As for infrastructure, we must put the infrastructure where the people want to go. It is very expensive. If we put the infrastructure somewhere where nobody wants to go, then it is really a waste of resource. Coming to research and development, the rate of obsolescence in electronics is so high that we have to identify the institutions whom we will fund and who will also come in with a matching contribution because giving money for nothing is no good. Those people must make a matching contribution. Then we have the Expert Committee, as you know very well, Sir, having been associated with this. The Expert Committee really identifies the institutions, areas, where these monies must be spent. Its advice is of a very great value and it is usually accepted in toto by the Department.

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है और उसके पीछे एक स्टेटमेंट भी उन्होंने दी है तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी पर गांधी नगर और अटीरा, इन दोनों के लिए गुजरात में, आपके जवाब में तो आपने बता दिया है कि कोई स्टेटवाइज ऐलोकेशन आप करते नहीं हैं। तो गुजरात सरकार ने आपके पास कोई प्रस्ताव भेजे हैं इन दोनों इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए और उनके लिए जो रकम मांगी गई है, वह केन्द्र सरकार उन्हें कब देने जा रही है और कितने पैसे उन्होंने मांगे हैं?

SHRI EDUARDO FALEIRO: Sir, we have a Software Technology Part and I must say that the Gandhinagar Software Technology Park is not among those seven that we have throughout the country. *(Interruption)*.

SHRI ANANTRAY DEVSHANKAR DAVE: For further development.

SHRI EDUARDO FALEIRO: The development which is there is not being utilised. That is the point. In an advanced State like Gujarat, the Software Technology Park which is there with data-speed facilities, all the communication system and so many other facilities, is not being fully utilised. We have others who have been doing far better. The point I am making is this. We have submitted a report to the

Government of Gujarat on how to improve on the production of electronic goods and services in that State which is so advanced otherwise. The report has been sent by the Department of Electronics to the State of Gujarat, to their Government, on how to improve on this. As far as the facilities which are there are concerned, they are good enough and they should be better utilised. If anything more is to be done which will be efficiently and fully utilised, surely we will do it.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Mr. Chairman, Sir, the Government has invested a lot of money in creating infrastructure on the ground. We have a lot of electronic cities. In my State, we have one. But we do not have satellite communications. When the multinationals come from abroad, they want to set up their industry with a local collaboration. The main drawback is that we do not have the telecommunication facilities so that they can connect them to the master computers overseas. I do not think any investment has been made in this sector. Most of them shy away. We have many examples. Many of our electronic cities, including the electronic city in the constituency of the hon. Minister in Goa, are lying idle. I want to know what steps the Government will take to see that our satellite telecommunication system is improved so that we may discourage the imported screw-driver technology and encourage our local indigenous industry.

SHRI EDUARDO FALEIRO: We have set up seven Software Technology Parks under the Department of Electronics. Due to the constraint of funds, it is not possible immediately for the Department to set up more such Parks. I must mention here that some State Governments have set up this facility on their own. I must mention, for instance, the Government of Kerala. The Government of Andhra Pradesh also, if I am not mistaken, has done something on its own. The Government of Kerala has contributed a lot. Now, even individuals like the NRIs have created these facilities like, for instance, in Pune. Now the direction seems to be that the State Governments are creating these facilities for the benefit of their own States and individuals, NRIs and others, have also been creating these facilities.

A lot of incentives are given in respect of imported equipments and so on so that the facilities are created by the State Government, the NRIs and other individuals. As far as the State which the hon. Member referred to is concerned, we are going to do something, not necessarily by this Department, but through the Ministry of Industry, in a collaborative manner, and some substantial advance, with the help of the State Government, I hope, will be achieved, in the near future.

नौसेना अकादमी की स्थापना

*224. श्री जनेश्वर मिश्र: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्थायी नौसेना अकादमी की स्थापना करने की कोई परियोजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस अकादमी की स्थापना करने का नीतिगत निर्णय कब लिया गया था और उस समय इस कार्य पर कितनी लागत आने का अनुमान था;

(ग) क्या सरकार इस परियोजना पर कार्य कर रही है, और यदि हां, तो परियोजना पूर्ण होने तक इसकी लागत कितनी होगी; और

(घ) इस परियोजना को कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इसका तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने मई, 1982 में एझिमाला में एक स्थायी नौसेना अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया था । चूंकि तब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी, अतः इस प्रयोजन के लिए 1980—85 की नौसेना योजना में अनन्तिम रूप से 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।